अफ्रीकी नागरिकों के शव 10 दिन सड़ाने के बाद स्थानीय मेडिकल कॉलेज के बजाय रोहतक भेजे गये

फरीदाबाद (म.मो.) पिछले दिनों तथाकथित पुलिस मुठभेड़ में मारे गये अफ्रीकी मूल के एक पुरुष व रेलवे पुलिस द्वारा बीके अस्पताल में लाये गये एक अफ्रीकी महिला के शव को करीब 10 दिन तक बीके अस्पताल के शवगृह में रख कर वारिसान का इन्तज़ार किया गया। लेकिन कोई नहीं आया। यहां तक कि किसी अफ्रीकी दूतावास ने उन्हें अपना नागरिक तक नहीं माना। उनसे बरामद पासपोर्ट को भी नकली बता दिया।

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार विदेशी शवों को इतने समय के बाद भी ठिकाने नहीं लगाया जा सकता। लेकिन बीके अस्पताल में और अधिक समय तक रखना संभव नहीं था क्योंकि ये सड़ने लगे थे। ऐसे में इन्हें विशेष वातानुकूलित गाड़ी से रोहतक मेडिकल कॉलेज भेजा गया ताकिं इन शवों को विशेष प्रकार का इन्जेक्शन व लेप लगाकर लम्बे समय तक रखा जा सकेगा। जाहिर है करीब 100 किलोमीटर दूर इन शवों को ले जाने में हज़ारों रुपये के संसाधन में खर्च किये गये। साथ में जो 2-4 कर्मचारी गये उनका खर्च अलग से।

इस खर्च को व्यर्थ बताया जा रहा है क्योंकि जो काम रोहतक मेडिकल कॉलेज में होना है वही काम बल्कि उससे बेहतर स्थानीय ईएसआई मेडिकल कॉलेज में भी हो सकता है, जो ऐन बीके अस्पताल से सटा हुआ है, जहां शवों को ले जाने पर कोई खर्च नहीं आता। इससे एक ओर जहां रोहतक मेडिकल कॉलेज का कार्यभार जो पहले से ही काफ़ी बढा हुआ है, वह कम होता; दूसरे स्थानीय मेडिकल कॉलेज के छात्रों को सीखने के लिये जो इस तरह के शवों की जरूरत रहती है, वह कुछ हद तक पूरी होती।

इतना ही नहीं आज हर फ़ॉरेन्सिक जांच के लिये स्थानीय पुलिस को रोहतक भागना पड़ता है, वह सब स्थानीय मेडिकल कॉलेज में संभव है। यहां भी बाकायदा फ़ारेन्सिक विभाग की पूरी फ़ैकल्टी है जो छात्रों को यह विषय पढाती है। यदि इनको पुलिस के वास्तविक केस भी मिलें तो थ्योरी के साथ-साथ इनका प्रैक्टिकल भी हो जाय।

बीके अस्पताल में डॉक्टरों के घोर अभाव के बावजूद करीब 1100-1200 पोस्टमार्टम भी साल में करने होते हैं। यदि यह काम स्थानीय मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया जाय अथवा कुछ केस दे दिये जायें तो बीके अस्पताल को तो राहत मिलेगी सो मिलेगी, मेडिकल छात्रों द्वारा पोस्टमार्टम का कोटा भी पूरा हो सकेगा। फ़िलहाल इस कोटे को पूरा करने के लिये मेडिकल कॉलेज ने बीके अस्पताल को अपने साथ जुड़ा हुआ दिखा रखा है। लेकिन यह गठबंधन, एमसीआई मानकों के मुताबिक 31 दिसम्बर के बाद नहीं चल पायेगा। हरियाणा सरकार में किसी को इसकी चिंता नहीं सब खाये अघाये मस्त पड़े हैं। मस्ती से जब फुर्सत मिलती है तो लच्छेदार भाषणों से जनता को बहलाने फुसलाने का प्रयास किया जाता है।

स्थानीय मेडिकल कॉलेज अधिकारियों द्वारा इस बाबत हरियाणा सरकार को कई बार लिखा जा चुका है। परन्तु लिखे को पढने की फुर्सत किसके पास है। जिस बाबू के पास फुर्सत होती भी है वह उसे या तो ठंडे बस्ते में रख देता है या कोई एतराज लगा कर वापस कर देता है। ऐसे में यहां से कई बार वरिष्ठ डॉक्टर चंडीगढ में बैठे उच्चाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से मिल कर समझा भी चुके हैं। उन्हें बताया जाता है कि इस मेडिकल कॉलेज को चलाने का केवल खर्चा ही तो भारत सरकार का उपक्रम (ईएसआईसी) उठा रहा है, 50 प्रतिशत सीटें तो हरियाणा सरकार की हैं और चिकित्सा सेवा तो हरियाणा की जनता को ही दी जा रही है। बड़ी मुश्किल से जब तक यह बात उच्चाधिकारियों के कुंद जहन में यह बात बैठती है तब तक उनका विभाग बदल चुका होता है। फ़िर नये सिरे से यही कवायद करनी पड़ती है।

मेडिकल कॉलेज व बीके अस्पताल के बीच पड़े भूखंड को किसी से तो जोड़ो

बीके अस्पताल के शवगृह वाली साइड व ईएसआई मेडिकल कॉलेज की दीवार के बीच एक तीन एकड़ का भूखंड कतई बेकार किन्ही अवैध कब्जों का इन्तज़ार कर रहा है। इससे पहले कि उस पर कोई 'राहुल कॉलोनी' बसे, इस भूखंड को बीके अस्पताल या मेडिकल कॉलेज के साथ जोड़ कर चारदिवारी के भीतर कर लेना चाहिये। इससे दोनों चिकित्सा संस्थानों की निकटता व सहयोग तो बढ़ेगा ही, मरीज़ों को चिकित्सा लाभ व दोनों ओर के स्टाफ़ को भी लाभ होगा। फ़िलहाल मेडिकल छात्रों एवं बीके अस्पताल के डॉक्टरों को एक दूसरे के यहां आने जाने में करीब 2 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है।

बल्लबगढ़ की चार कॉलोनियों को भी पकड़ाया विकास का चुनावी लॉलीपॉप

बल्लबगढ़ (म.मो.) बीते चार वर्ष के शासनकाल में भाजपाई नेताओं ने विकास के नाम पर नारियल फ़ोड़ने के अलावा और तो कुछ किया नहीं; अब चुनाव सिर पर आये तो जनता के बीच जा कर वोट मांगने के लिये जो तरह-तरह के शगूफ़े छोड़े जा रहे हैं, उन्हीं में से एक शिगूफ़ा में दावा किया गया कि यहां की चार कॉलोनियों-त्रिखा, रघुवीर, भाटिया व शिव कॉलोनी-के विकास के रास्ते खुल गये हैं। इसके लिये जश्न मनाने के साथ-साथ मुख्यमंत्री खट्टर का आभार प्रकट करने की भाजपाई तैयारियां चल रही हैं। यानी कि इन कॉलोनियों की 50 000 की आबादी से वोट मांगने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है।

अब देखने वाली बात यह है कि खट्टर सरकार ने ऐसा क्या इन लोग़ों को दे दिया जिसके अहसान तले दब कर ये लोग मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करें और आगामी चुनाव में भाजपा को वोट दें? ये तमाम कॉलोनिया 30 वर्ष से भी अधिक पुरानी हैं। सरकारों की ढुलमुल एवं जनविरोधी नीतियों के चलते प्राइवेट कॉलोनाइज़रों ने प्लॉट काट-काट कर इन कॉलोनियों को अवैध रूप से बसा दिया था। तहसीलदार मोटी रिश्वतें लेकर इन अवैध प्लॉटों की रजिस्ट्रियां करते थे। नगर निगम अथवा कॉम्पलेक्स के कर्मचारी यहां बने अवैध मकानों को न तोड़ने के नाम पर रिश्वत लेते थे। बिजली वाले अवैध बने घरों को कनेक्शन देने की अलग से रिश्वत लेते थे।

इस सबके बावजूद 'हूडा' (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) ने इन चारों कॉलोनियों की करीब 54 एकड़ ज़मीन के अधिग्रहण के नोटिस जारी कर दिये। यानी अब तक कॉम्पलेक्स के अलावा 'हूडा' वाले भी इन मकानों की तोड़-फ़ोड़ के अधिकारी हो गये। पिछले सभी चुनावों में हर पार्टी के उम्मीदवार ने इनकी वोटों के लिये इन्हें लारे लप्पे दिये। परन्तु किसी ने भी कुछ नहीं किया। यहां तक कि भाजपा के उम्मीदवार आनन्द शर्मा भी यहां से विधायक बने थे और भाजपा, पहले बंसी लाल फ़िर चौटाला सरकार में शामिल रही थी। लेकिन इन कॉलोनियों के लिये कुछ नहीं हुआ।

अब भी हुआ क्या है? केवल इतना कि 'हूडा' ने इस 54 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण करने की योजना समाप्त कर दी है जिसे अंग्रेजी में डिनोटिफ़िकेशन कहा जाता है। इस पर सरकार की कोई लागत नहीं लगती, सिर्फ़ 2-4 कागज़ ही काले करने पड़ते हैं। वैसे भी सरकार एवं 'हूडा' के पास इसे डिनोटिफ़ाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बन चुके घरों को तोड़ना सरकार के बस का नहीं था जो लोग़ों ने अपने पैसे से प्लॉट खरीद कर तहसील में रजिस्ट्री करा कर बनाये हों। कहा जा रहा है कि अब इन कॉलोनियों में विकास की बयार बहेगी।

इस बयार का नमूना जवाहर कॉलोनी, पंजाबी कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी व पर्वतीया कॉलोनी आदि में देखा जा सकता है। इस बयार को चलाने के नाम पर बाकायदा वहां के निवासियों से प्रति गज़ के हिसाब से विकास शुल्क वसूला गया था, उसके बावजूद भी वहां की सड़कों, सीवर व पानी को लेकर बहुत ही दयनीय स्थिति है। और तो और बिजली की सप्लाई भी राम भरोसे ही रहती है।

इसलिये कॉलोनी वासियों को न तो बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत है और न ही मुख्यमंत्री खट्टर एवं विधायक मूल चंद के अहसान का बोझ ढोने की।

बिजली को लेकर और कितना झूठ बोलेगी सरकार? बीते चार साल से लारे लप्पे ही दिये जा रहे हैं!

फ़रीदाबाद (म.मो.) शायद ही कोई दिन निकलता होगा जब शहर के विभिन्न भागों में बिजली सप्लाई अवरुद्ध न होती हो, वह भी थोड़ी बहुत देर के लिये नहीं कई-कई घंटों के लिये। कभी बिजली की कमी तो कभी लोकल फ़ाल्ट्स को कारण बताया जाता है। जब से अडानी जैसी प्राइवेट कम्पनियों से बिजली खरीदने का सिलसिला शुरू हुआ है तब से बिजली की कमी तो नहीं होती लेकिन लचर वितरण व्यवस्था एवं लोकल फ़ाल्ट्स के चलते सप्लाई अवरुद्ध होती रहती है।

पिछले कई बरसों, खासकर भाजपा शासन काल में आये दिन घोषणा होती आ रही है कि अब फ़लां सब स्टेशन बनने जा रहा है, फ़लां चालू हो गया है, फ़लां नई ट्रासमिशन लाइन चालू कर दी गयी है जिससे उपभोक्ताओं को निर्बाध सप्लाई का लाभ मिलेगा। और तो और गत दिनों स्थानीय विधायक सीमा त्रिखा ने बिजली अधिकारियों की मीटिंग बुला कर जो ड्रामेबाज़ी की थी उसकी भी पोल खुल चुकी है उस ड्रामेबाज़ी में कहा गया था कि नागरिकों को चौबिसों घंटे निर्बाध बिजली मिलेगी, फ़ाल्ट होने पर रात में ही उसे ठीक किया जायेगा, इसके लिये विशेष टीमें गठित कर दी गयी हैं।

लेकिन '**मज़दूर मोर्चा**' ने तुरंत बता दिया था कि ये सब झूठ बोल कर जनता को बहका रहे हैं। वास्तव में इनके पास न तो पर्याप्त स्टाफ़ है न ही आवश्यक साजो सामान। इन दोनों चीज़ों का प्रबन्धन न तो स्थानीय बिजली अधिकारियों के हाथ में है और न ही विधायकों एवं सांसदों के हाथ में। इसके लिये मुख्यमंत्री के स्तर पर नीतिगत फ़ैसले लिये जाने चाहिये। हैं।

25 जुलाई को बिजली विभाग के एस.ई. ऑपरेशन ने पत्रकारों को बताया कि स्टाफ़ की भारी कमी के चलते वे समय पर फ़ाल्ट ठीक नहीं कर पा रहे थे। इसके लिये अब एक प्राइवेट कम्पनी को ठेका दे दिया गया है जिसे शीघ्र ही काम अलॉट कर दिया जायेगा। यानी कि अब तक सब झूठ बोला जा रहा था।

सच तो अब भी अधूरा ही है। महकमे का अपना स्टाफ़ तो बीसियों वर्ष से कम से कमतर होता जा रहा है जिसके बदले ठेकेदारी में ही स्टाफ़ को रखा जा रहा है। ठेकेदारी स्टाफ़ का पहला फ़ायदा तो सरकारी अफ़सरों व नेताओं का यह होता है कि कोई भी ठेका प्राप्त करने के एवज में अच्छा-खासा कमीशन देता है। दूसरे, ठेकेदारी कर्मचारी निरीह प्राणी होते हैं उन्हें आधे अधूरे वेतन पर रख कर 12 से 16 घंटे तक रगड़ा जाता है। इस तरह के कर्मचारी पूरी तरह ट्रेंड भी नहीं होते इसलिये वे कहीं और काम के लायक नहीं होते। इन्हीं वर्करों को विभागीय अधिकारी खतरनाक कामों पर लगा देते हैं जिसके चलते जानलेवा हादसों की संख्या बढती जा रही है।

असली सच तो यह है कि इस शासन-प्रशासन में कोई सुधार संभव नहीं, केवल झूठ के पकौड़े ही खाने को मिलेंगे और चुनावी जुमले सुनने को।

जल भराव से पीएफ कार्यालय ठप, अखबार भी नहीं बंटे

फरीदाबाद (म.मो.) चंद घंटों की बारिश ने शहर भर का जो हाल बेहाल किया सो किया, भारत सरकार सैक्टर-15ए स्थित ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि) कार्यालय भी ठप होकर रह गयाँ वीरवार को प्रात: हुई हल्की बारिश ने इस दफतर के परिसर में डेढ़ से दो फीट तक पानी भर दिया। इसके चलते खंबे से आने वाली बिजली की केबल ब्रेस्ट हो गयी जिससे दफतर की बिजली फेल हो गयी। वीरवार सारे दिन में यह केबल ठीक नहीं हो पाई। शुक्रवार को और भी घनी बारिश के चलते केबल को बदलना संभव नहीं था। इसके चलते पूरे दो दिन कार्यालय पूरी तरह से ठप रहा, वहां कोई कामकाज नहीं हो पाया।

जलभराव की तरह केबल के ब्रस्ट होने के पीछे भी सरकारी मशीनरी में व्याप्त हरामखोरी व रिश्वतखोरी है। यदि ऐसा न होता और ठीक से काम हुए होते तो जलभराव नही हो सकता था और यदि कमीशनखोरी के चक्कर में घटिया केबल न खरीदी गयी होती तो वह ब्रर्स्ट नहीं होती।

सड़कों व गलियों में जलभराव के चलते सुबह सवेरे घरों में अखबार डालने वाले हॉकर निकल ही नहीं पाये। निकलना संभव भी नहीं था। साइकिल के आगे-पीछे 20-20 किलोग्राम अखबार लाद कर डेढ़ से दो फीट खड़े पानी में साइकिल चलाना संभव नहीं हो पाता। इसके चलते अखबार कम्पनियों की ओर से छाप कर भेजे गये लाखों रूपए के अखबार रद्दी बनकर रह गये। इससे हॉकरों की दिहाड़ी तो मारी जाती ही है और मोटा खमियाजा अखबारों के एजेंटों को भुगतना पड़ा। ऐसा न तो पहली बार हुआ है और न ही आखिरी बार। साल में चार-पांच बार तो ऐसा जरूर होता है। परन्तु शासन प्रशासन को इसकी कोई परवाह नहीं।